Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

अक्टूबर 2022

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा 3

- 36वें राष्ट्रीय खेलों में भीम अवार्डी अनीश भनवाला ने शूटिंग में जीता गोल्ड मेडल 3
- स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल 3
- नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में राष्ट्रपति ने करनाल के मंदीप सिंह चौहान को रजत कमल से नवाजा 4
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2022 में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर 4
- झज्जर के बॉक्सर भारत जून का यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ चयन 5
- गुरुग्राम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन 5
- चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा-2021 पुरस्कार 6
- नीदरलैंड्स की तकनीक पर गुरुग्राम में बनाई जाएगी फूल की निर्यात मंडी 6
- 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में हरियाणा ने जीता पहला स्वर्ण पदक 7
- मुख्यमंत्री ने विज्ञापन अनुमति व नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी हेतु लॉन्च किया एक पोर्टल 7
- 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन दिवस पर बॉक्सिंग मुकाबलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते 4 स्वर्ण पदक 8
- कचरे के निस्तारण के लिये हरियाणा में स्थापित होंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट 9
- हरियाणा में अब भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जानी जाएंगी चौपालें 9
- हरियाणा के 20 लाख किसानों को मिली 340 करोड़ रुपए की सम्मान निधि 10
- हरियाणा में खुलेगा 'ब्यूरो ऑफ सिविल एवियेशन सिक्योरिटी' सेंटर 10
- ज़िला जल संसाधन योजना 2022-25 11
- हरियाणा ने पालम विहार को जोड़ने वाली मेट्रो विस्तार परियोजना के लिये अंतिम डीपीआर को दी मंज़ूरी 11
- फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम, 2022 12
- हरियाणा कारागार नियम, 2022 12
- हरियाणा में स्थापित होंगे 6 ऑटोमेटिड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन 13
- नेचुरल गैस का उपयोग करने वाली हरियाणा की औद्योगिक इकाईयों को वैट में 50 प्रतिशत मिलेगी छूट 13
- कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल एप 14
- हरियाणा सरकार ने बच्चों को शिक्षा एवं रोज़गार देने के लिये एक नया मैकेनिज्म तैयार किया 14
- हरियाणा से देश के सात राज्यों के 11 प्रमुख शहरों के लिये होगी सीधी उड़ान शुरू 15
- कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में सूर्यग्रहण पर पैनल प्रदर्शनी 16
- HAU ने गेहूँ की किस्म WH1270 का बीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिये 9 कंपनियों से किया समझौता 17
- केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया 17
- फरीदाबाद में बने आधुनिक बस अड्डे का शुभारंभ 18
- एनजीटी द्वारा कचरा प्रबंधन को लेकर गठित कमेटी की तीसरी बैठक गुरुग्राम के बंधवाड़ी में आयोजित 18
- आपात स्थिति में हर ज़िले में हेलीपैड सुविधा प्रदान करने वाला हरियाणा बनेगा देश का पहला राज्य 19

नोट :

हरियाणा

36वें राष्ट्रीय खेलों में भीम अवार्डी अनीश भनवाला ने शूटिंग में जीता गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को हरियाणा के करनाल ज़िले के शूटर अनीश भनवाला ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया।

प्रमुख बिंदु

- अनीश भनवाला ने यह मेडल 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन मुकाबले में हासिल किया है।
- विदित है कि भीम अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज़ अनीश भनवाला ने बीते अगस्त माह में जर्मनी में चौथी सुहलर कप शूटिंग प्रतियोगिता में दो कांस्य पदक जीत कर देश व प्रदेश का मान बढ़ाया था। साथ ही दक्षिण कोरिया के चांगवान में आइएसएसएफ निशानेबाज़ी विश्व कप प्रतियोगिता के 25 मीटर रैपिड फायर मिक्स इवेंट में वह रजत पदक जीत चुके हैं।
- इसके अलावा इसी वर्ष मार्च माह में मिस्र के काहिरा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स विश्व चैंपियनशिप के मुकाबलों के दौरान अनीश ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है।
- छोटी उम्र में अनीश की उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने उन्हें भीम अवार्ड से नवाजा है। वर्ष-2018 के कामनवेल्थ खेल में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी अनीश दो बार राष्ट्रपति से अवार्ड हासिल कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सम्मान प्राप्त कर चुके हैं।
- उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था, जोकि देश में सात साल बाद आयोजित हो रहे हैं। ये खेल गुजरात के अहमदाबाद के अलावा, गांधीनगर, सूरत, वड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में हो रहे हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

1 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप 100 शहरों में गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, पंचकूला व अंबाला शामिल हैं। वहीं धारूहेड़ा को (25,000-50,000 जनसंख्या) और बवानी खेड़ा को (15,000-25,000 जनसंख्या) में फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है। कैंटोनमेंट बोर्ड आधारित रैंकिंग में हरियाणा का अंबाला कैंट 25वें स्थान पर है।
- विदित है कि 2021 की तुलना में हरियाणा की परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा 8वें स्थान पर था।
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और विभिन्न सरकारी कार्यालयों, नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी का नतीजा है कि राज्य में लगातार स्वच्छता के स्तर में सुधार हो रहा है।

नोट :

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में राष्ट्रपति ने करनाल के मंदीप सिंह चौहान को रजत कमल से नवाजा

चर्चा में क्यों ?

1 अक्टूबर, 2022 को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड वितरण समारोह में हरियाणा के करनाल ज़िले के मंदीप सिंह चौहान को उनके द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- फिल्म निर्माता मंदीप सिंह चौहान को यह सम्मान उनकी लघु फिल्म 'जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड' के लिये दिया गया। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चयनित की गई थी।
- मंदीप सिंह चौहान के साथ फिल्म के निर्देशक मुंबई निवासी कामाख्या नारायण सिंह को भी राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया।
- उल्लेखनीय है कि 2020 के नेशनल फिल्म अवार्ड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित किये गए थे और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में यह पुरस्कार वितरित किये गए। इसी समारोह में देश का फिल्म जगत् का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दादा साहब फालके अवॉर्ड प्रख्यात अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया।
- विदित है कि नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त करने वाले मंदीप सिंह चौहान मूलत: करनाल ज़िले के गोंदर गाँव से संबंध रखते हैं। मनदीप सिंह चौहान 'बॉलीवुड में हिन्दी' सहित कई चर्चित डॉक्युमेंट्री फिल्म्स के सहायक निर्माता के रूप में कार्य करने के कई क्षेत्रीय व राष्ट्रीय समाचार चैनलों के साथ जुड़े रहे हैं।
- ज्ञातव्य है कि मंदीप सिंह चौहान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म हिंदी में निर्मित 'जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड' जम्मू कश्मीर में संविधान के अब समाप्त हो चुके अनुच्छेद 35-ए के काले प्रावधानों के कारण वहाँ के वाल्मीकि समुदाय के साथ दशकों तक हुए अमानवीय अत्याचारों की दास्तान है।
- जम्मू-कश्मीर मामलों पर वर्षों तक लेखन करते रहे डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान बताते हैं कि अनुच्छेद 370 के संशोधन और 35-ए के उन्मूलन ने राधिका जैसे लाखों लोगों के जीवन में नई रोशनी का संचार किया।
- उन्होंने कहा कि चोरी छुपे जोड़े गए अनुच्छेद 35-ए के कारण राधिका गिल सहित वहाँ के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार तो दूर की बात, सरकारी नौकरियों के लिये आवेदन करने का अधिकार भी नहीं था। यह काला अनुच्छेद उन्हें केवल और केवल सफाई कर्मचारी बनने की इजाजत देता था।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2022 में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर

चर्चा में क्यों ?

2 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2021-22 में संपूर्ण स्वच्छता हेतु ओडीएफ स्थायित्व तथा ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2022 के आधार पर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा ने यह स्थान देश में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में हासिल किया है।
- विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा राज्य की ओर से ये पुरस्कार राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया।
- विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि इस अर्जित उपलब्धि में विकास एवं पंचायत विकास के अधिकारियों के साथ-साथ स्वच्छता सैनिकों, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामुदायिक सहयोग करने वाले लोगों व संस्थाओं का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक पूरे देश में हर साल स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है।

नोट :

- इसी अवधि के दौरान राज्य में भी जिला स्तरीय 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत हर गाँव में स्वच्छता अभियान चलाए गए और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने व अपने परिवेश को साफ-सुथरा रखने के बारे में रैलियाँ, प्रभात फेरियाँ, हस्ताक्षर अभियान, सामुदायिक सहयोग व अन्य माध्यमों से जागरूक किया गया।
- देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि भिवानी जिला पूरे देश के ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। भिवानी ज़िले के 22 गाँवों में बरसाती व गंदे पानी का विशेष स्ट्रक्चर बनाकर प्रबंधन किया गया है। इसके साथ-साथ ज़िले के विभिन्न गाँवों में अमृत सरोवर परियोजना के तहत 24 तालाबों का नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार शहरों की तर्ज पर गाँवों में भी हर घर से कूड़ा उठाने की दिशा में योजना भी बना रही है।

झज्जर के बॉक्सर भारत जून का यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ चयन

चर्चा में क्यों ?

3 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के झज्जर ज़िले के बॉक्सर भारत जून का स्पेन में आयोजित होने वाली यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप (14 नवंबर से 26 नवंबर तक) में चयन होने की जानकारी उनके कोच हितेश देशवाल ने दी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि भारत जून ने गुवाहाटी में संपन्न हुई यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिये भाग लिया था। वहीं, अब उनका चयन भारतीय मुक्केबाजी यूथ टीम में हुआ है, जिससे अब वह स्पेन में आयोजित होने वाली यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेगा।
- कोच हितेश देशवाल ने बताया कि भारत जून ने सर्बिया में 12 से 19 सितंबर तक चलने वाले 92 प्लस मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। सर्बिया में उनका यह तीसरा स्वर्ण पदक था। भारत जून ने इससे पहले एशियन खेलों में भी दो स्वर्ण पदक जीते हैं।

गुरुग्राम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

4 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के गुरुग्राम ज़िले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन 7 से 23 अक्टूबर, 2022 तक सैक्टर-29 स्थित लेजरवैली ग्राउंड में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यहाँ पर देश के 27 राज्यों की कला व संस्कृति के उत्पादों की 250 से अधिक स्टॉल लगाई जाएंगी। खाने-पीने के शौकीन लोगों के लिये अलग-2 राज्यों के 30 लाइव फूड स्टॉल अलग से लगाएँ जाएंगे। एक प्रकार से इस मेले में आने वाले लोगों को मिनी भारत के दर्शन होंगे, जहाँ पर अलग-2 राज्यों के लोकप्रिय उत्पादों के अलावा स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वहाँ की संस्कृति को जानने व समझने का पूरा अवसर मिलेगा।
- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिये रोजाना अलग-2 विषयों पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएंगी ताकि वे अपने उत्पादों की बिक्री करने व मार्किटिंग आदि के स्किल विकसित करके ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
- उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बेहतर व प्रभावी मार्किटिंग के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय अपना ई-कॉमर्स प्लैटफार्म जल्द ही शुरू करने जा रहा है। अभी तक ये उत्पाद ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट तथा अन्य ऑनलाइन साइटों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए जा रहे थे।

चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा-2021 पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

5 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में आयोजित 'चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा-2021' कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 'चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा-2021 पुरस्कार' प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली चयन समिति की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मनोहर लाल हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें यह गौरव मिला है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पिछले आठ वर्षों में सुशासन के माध्यम से हरियाणा की कार्यप्रणाली व प्रशासनिक दक्षता की तस्वीर बदलने के लिये किये गए प्रयासों पर ही चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा-2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- विश्व में बड़े बदलाव प्रेरक के रूप में विख्यात राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय नेल्सन मंडेला के नाम पर गठित गाँधी-मंडेला फाउंडेशन व बदलाव के लिये राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कार देने वाली संस्था इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया गया।
- ज्ञातव्य है कि इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी नामक संस्था अगले वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 'ग्लोबल चैंपियन ऑफ चेंज' कार्यक्रम का भी आयोजन करने जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि संस्था का यह 5वाँ संस्करण था, जिसमें मुख्यमंत्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव के प्रेरक बने 25 अन्य विभूतियों को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा-2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- पहला संस्करण 26 दिसंबर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा यह पुरस्कार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दिया गया था। इसी प्रकार दूसरे संस्करण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को; तीसरे संस्करण में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को जबकि चौथे संस्करण में 30 सितंबर, 2021 को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल को सम्मानित किया गया था।
- चयन समिति अपनी प्रक्रिया के तहत 6 महीने की अवधि में लोगों से फीडबैक के आधार पर पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित करती है और फिर चयन समिति के सदस्य आवेदनों का आकलन करते हैं और संस्थानों को चयनित नाम भेजते हैं।
- गाँधी-मंडेला अवार्ड के लिये चयन समिति के सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. के.जी. बालाकृष्णन, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केदारनाथ उपाध्याय, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद तफज्जुल इस्लाम तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा शामिल हैं।

नीदरलैंड्स की तकनीक पर गुरुग्राम में बनाई जाएगी फूल की निर्यात मंडी

चर्चा में क्यों?

6 अक्टूबर, 2022 को गुरुग्राम ज़िला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि हरियाणा के कृषि तथा पशुपालन मंत्री जेपी दलाल द्वारा एक आधुनिक वैश्विक फूल मंडी गुरुग्राम ज़िले में बनाए जाने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि कृषि तथा पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ नीदरलैंड्स स्थित अलसमीर फ्लोरा मार्केट का दौरा किया था।

- उन्होंने कहा कि नीदरलैंड्स स्थित फूल मार्केट की तकनीक पर आधारित गुरुग्राम में भी फूल मंडी बनाई जाएगी तथा इस मंडी से फूल विदेश निर्यात किये जाएंगे। इससे हरियाणा सहित एनसीआर के फूल उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- उल्लेखनीय है कि नीदरलैंड्स की फूल मंडी में रोज़ाना 440 लाख फूल आते हैं। इनमें 30 प्रतिशत फूल स्थानीय तथा 70 प्रतिशत फूल अन्य देशों से बिक्री के लिये आते हैं। इनकी सुबह छह से नौ बजे तक ऑनलाइन बोली लगती है।
- किसानों के लिये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। ज़िले में बनाई जाने वाली मंडी का अधिकतर हिस्सा वातानुकूलित होगा। मंडी में फूलों के स्टोरेज के लिये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फर्रुखनगर और पटौदी क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान फूल उत्पादन का काम करते हैं। शहर में फूल मंडी न होने के कारण इनको अपने फूल गुरुग्राम या दिल्ली जाकर सस्ते दामों में बेचने पड़ते हैं।

36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में हरियाणा ने जीता पहला स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों?

9 अक्टूबर, 2022 को गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में हरियाणा ने पहला स्वर्ण पदक जीता है।

प्रमुख बिंदु

- गुरुग्राम के राहुल और रिशभ ने योगासन में अपनी प्रतिभा का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।
- इसके अलावा, योगासन में आर्टिस्टिक सिंगल इवेंट में राज्य के ही प्रवीन पाठक ने कांस्य पदक जीता।
- राज्य के खिलाड़ियों का नेशनल गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्ञातव्य है कि 9 अक्टूबर शाम 6 बजे तक हरियाणा के खाते में 31 स्वर्ण पदक, 29 रजत और 34 कांस्य पदक आ चुके थे।
- अभी तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक्युएटिक्स में 1 रजत और 1 कांस्य, तीरंदाज़ी में 5 स्वर्ण, एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य, साइकिलिंग में 2 स्वर्ण और 3 रजत, फेंसिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, गोल्फ में 2 रजत और 3 कांस्य, जूडो में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 9 कांस्य, कबड्डी में 2 कांस्य, नेट बॉल में 2 स्वर्ण, रोइंग में 3 रजत और 1 कांस्य, रग्बी में 1 स्वर्ण, शूटिंग में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य, सॉफ्ट टेनिस में 1 कांस्य, टेबल टेनिस में 1 रजत, टेनिस में 1 कांस्य, वेटलिफ्टिंग में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य, कुश्ती में 12 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य तथा योगासन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं।

मुख्यमंत्री ने विज्ञापन अनुमति व नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी हेतु लॉन्च किया एक पोर्टल

चर्चा में क्यों?

11 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारियों व नागरिकों को एक और सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा म्युनिसिपल विज्ञापन उपनियम-2022 के तहत विज्ञापन अनुमति तथा नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिये एक पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल के लॉन्च होने से सभी नगर निकायों में विज्ञापन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सरकारी भवनों व प्राइवेट भवनों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
- उन्होंने बताया कि सभी नगर निकायों को कलेक्टर रेट का 2 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। सरकारी स्थलों का ई-ऑक्शन किया जाएगा। इसका न्यूनतम रेट 4 प्रतिशत होगा, जिसमें से 40 प्रतिशत एमसी को और 60 प्रतिशत भवन मालिक को मिलेगा।
- राज्य में सभी नगर निकाय, सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण अब विज्ञापन हेतु ई-नीलामी के लिये अपनी संपत्तियों को पोर्टल पर सूचीबद्ध कर सकते हैं। निजी संपत्ति मालिक भी ई-नीलामी के माध्यम से विज्ञापन अनुमति देने के लिये इस पोर्टल पर अपनी संपत्ति/संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का विकल्प चुन सकते हैं।

- नगर निकायों की भूमिका केवल इस पोर्टल पर आवेदनों को संसाधित करने और संपत्तियों को सूचीबद्ध करने, आरक्षित मूल्य भरने तथा नीलामी की तिथि निर्धारित करने की होगी। इसके बाद पोर्टल पर स्वतः ही नीलामी आयोजित होगी और उच्चतम बोली लगाने वाले का चयन होगा।
- इसके अलावा, सभी विज्ञापन अनुमतियाँ, अनुबंध, भुगतान, प्रतिभूतियों का प्रबंधन इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे मज़बूत राजस्व संग्रहण और अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि एक बार पोर्टल पर पंजीकृत विज्ञापन संस्थाएं (व्यवसाय/व्यक्ति) राज्य में नगर निकायों में सभी सूचीबद्ध विज्ञापन संपत्तियों की ई-नीलामी में भाग ले सकती हैं।
- यह पोर्टल न केवल विज्ञापन अधिकार प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि नगर निकायों और अन्य सरकारी संस्थाओं की विज्ञापन के माध्यम से राजस्व में भी वृद्धि करेगा।

36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन दिवस पर बॉक्सिंग मुकाबलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते 4 स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

12 अक्टूबर, 2022 को गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन दिवस पर खेले गए बॉक्सिंग के मुकाबलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 10 पदक जीते।

प्रमुख बिंदु

- बॉक्सिंग के मुकाबलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 काँस्य पदक जीते। 80 किलोग्राम भार वर्ग में विनीत, अंकित ने तथा लड़कियाँ में मीनाक्षी और पूनम ने स्वर्ण पदक जीते।
- इनके अलावा, 57 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन ने रजत पदक, 92 किलोग्राम भार वर्ग में नवीन ने रजत पदक, 67 किलोग्राम भार वर्ग में सागर, जैसमीन और स्वीटी ने रजत पदक जीते, वहीं मोहित ने काँस्य पदक जीता।
- 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 116 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। सबसे खास बात यह रही कि 38 स्वर्ण पदकों में से हरियाणा ने 37 स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में जीते हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से दोगुने से भी ज्यादा हैं।
- पिछले 3 संस्करणों में हरियाणा के पदकों की संख्या इस बार सबसे अधिक रही है। विदित है कि पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 107 खेलों में जीत हासिल की थी।
- हालाँकि, पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा, परंतु कुल पदक विजेताओं में से 80 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व हरियाणा से ही है।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार की खेल नीति के अनुसार पुरस्कार व नौकरियाँ दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों की मेहनत के बल पर ही हरियाणा की खेलों के क्षेत्रों में ऐसी पहचान बनी है तथा अन्य राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करने लगे हैं।
- राज्य के खिलाड़ियों ने 38 स्वर्ण, 38 रजत और 40 काँस्य जीते हैं। खिलाड़ियों ने एक्युएटिक्स में 1 रजत और 1 काँस्य, तीरंदाजी में 5 स्वर्ण, एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 काँस्य, बॉक्सिंग में 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 काँस्य, कैनॉइंग में 1 रजत और 1 काँस्य, साइकिलिंग में 2 स्वर्ण और 3 रजत, फेंसिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 काँस्य, गोल्फ में 2 रजत और 2 काँस्य, हॉकी में 1 स्वर्ण, जुडों में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 11 काँस्य, कबडन्नी में 2 काँस्य, नेट बॉल में 2 स्वर्ण, रोइंग में 3 रजत और 1 काँस्य, रग्बी में 1 स्वर्ण, शूटिंग में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 काँस्य, सोफ्ट टेनिस में 2 काँस्य, टेबल टेनिस में 1 रजत, टेनिस में 1 काँस्य, वेटलिफ्टिंग में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 काँस्य, कुश्ती में 12 स्वर्ण, 7 रजत और 4 काँस्य, वुशू में 1 स्वर्ण और 2 रजत, वॉलीबॉल में 1 काँस्य तथा योगासना में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 काँस्य पदक जीते हैं।

नोट :

कचरे के निस्तारण के लिये हरियाणा में स्थापित होंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट

चर्चा में क्यों ?

13 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई सचिवों की समिति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट लगाने की मंज़ूरी मिली है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने बताया कि स्वच्छता अभियान को और गति प्रदान करने के लिये राज्य में कचरे के निस्तारण हेतु जल्द ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किये जाएंगे।
- एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में तीन क्लस्टरों के लिये तीन कार्यान्वयन एजेंसी के चयन को मंज़ूरी प्रदान की गई। प्रारंभिक चरण में भिवानी, सिरसा और करनाल क्लस्टर में यह प्लांट स्थापित किये जाएंगे।
- भिवानी क्लस्टर में 5 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार, करनाल क्लस्टर में 16 तथा सिरसा में 3 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है।
- संजीव कौशल ने बताया कि राज्य के सभी ज़िलों को 13 क्लस्टर में बाँटा गया है। इन क्लस्टर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ क्रियान्वित की जाएंगी।
- यह परियोजनाएँ ओपन टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। ओपन टेक्नोलॉजी में एजेंसी द्वारा कचरे के निस्तारण के लिये बायो-मेथेनेशन प्लांट, कम्पोस्ट प्लांट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जा सकेंगे।
- मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि एजेंसी द्वारा कचरे का डोर-टू-डोर कलेक्शन, कचरे को द्वितीय स्तर तथा प्लांट तक पहुँचाना सख्ती से सुनिश्चित किया जाए, ताकि निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए।
- बैठक में बताया गया कि ये परियोजनाएँ दीर्घकालिक हैं। इसके तहत कचरे का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और निस्तारण किया जाएगा।

हरियाणा में अब भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जानी जाएंगी चौपालें

चर्चा में क्यों ?

16 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकूला ज़िले में पंचायती राज प्रकोष्ठ के सम्मेलन के दौरान घोषणा किया कि राज्य की सभी चौपालों को भविष्य में डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के गाँवों में पार्टीबाज़ी और जातीय तनाव को खत्म करने के लिये राज्य सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इसके तहत गाँवों में बनने वाली चौपालें किसी एक जाति अथवा संप्रदाय के नाम पर नहीं होंगी, बल्कि ऐसी चौपालों को भविष्य में डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा।
- पूर्व में जिन चौपालों के नाम अन्य नामों पर रखे गए हैं, उनके नाम में भी बदलाव होगा। यह प्रक्रिया मौजूदा पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव नतीजों के बाद लागू होगी।
- सम्मेलन के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि काफी लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि चौपालों के नाम किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष अथवा संप्रदाय के नाम पर रखे जा रहे हैं। ऐसा करने से गाँवों में तनाव बढ़ रहा है, आपसी झगड़े हो रहे हैं। इसलिये सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी चौपालों का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन के रूप में होगा।
- इसके लिये निर्वाचित पंचायतों को इस बारे में प्रस्ताव बनाकर देना होगा तथा पुरानी चौपालों का नाम बदलने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजना होगा।

नोट :

हरियाणा के 20 लाख किसानों को मिली 340 करोड़ रुपए की सम्मान निधि

चर्चा में क्यों?

17 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों को दो हज़ार रुपए की 12वीं किस्त जारी कर 340 करोड़ रुपए की सम्मान निधि का लाभ दिया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राज्य के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' स्कीम के तहत खेती करने के लिये 2018 से आर्थिक सहायता दी जा रही है तथा इससे पहले 11 किस्तों में हरियाणा के किसानों को 3754.67 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पास दो हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा के 97 प्रतिशत किसानों को पीएम किसान योजना का सीधे लाभ मिला है।
- उन्होंने बताया कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना छह हज़ार रुपए दिये जाते हैं। इसका भुगतान दो-दो हज़ार रुपए की तीन किस्तों में किया जाता है। यह पैसा सरकार द्वारा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है।
- पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त फरवरी 2019 में जारी हुई थी। इसके बाद दूसरी किस्त 2 अप्रैल, 2019, तीसरी अगस्त 2019, चौथी किस्त जनवरी 2020, पाँचवीं किस्त 1 अप्रैल, 2020 को जारी हुई। इसी प्रकार छठी किस्त 1 अगस्त, 2020, सातवीं किस्त दिसंबर 2020, आठवीं किस्त एक अप्रैल 2021, नौवीं किस्त 9 अगस्त, 2021, 10वीं किस्त जनवरी 2022, 11वीं किस्त मई 2022 और अब 12वीं किस्त 17 अक्टूबर, 2022 को जारी की गई है।
- ज्ञातव्य है कि पीएम मोदी ने दीवाली का तोहफा देते हुए देश के 12 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं को 16 हज़ार करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की है।

हरियाणा में खुलेगा 'ब्यूरो ऑफ सिविल एवियेशन सिक्योरिटी' सेंटर

चर्चा में क्यों?

18 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नई दिल्ली में नागरिक उडन्यन मंत्रियों की दोदिवसीय राष्ट्रीय बैठक के बाद बताया कि 'ब्यूरो ऑफ सिविल एवियेशन सिक्योरिटी' का सेंटर हरियाणा में खोला जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 'ब्यूरो ऑफ सिविल एवियेशन सिक्योरिटी' का सेंटर राज्य के हिसार ज़िले के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय या पॉलिटेक्निक में खोला जाएगा। इसके लिये जल्द ही आगे की औपचारिकता पूरी कर ली जाएंगी।
- उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार का एवियेशन-हब मार्च 2023 में क्रियान्वित हो जाएगा तथा इसके बाद इस एयरपोर्ट से अमृतसर, जालंधर, श्रीनगर, जम्मू, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, आगरा, वाराणसी, देहरादून तथा बिहार के गया के लिये उड़ान आरंभ की जाएंगी, ताकि राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और देश के सीमावर्ती ज़िलों से सैन्य-बलों के कर्मचारियों व अधिकारियों को आने-जाने में सुविधा हो सके।
- डिप्टी सीएम ने बताया कि गुरुग्राम में हेलीहब का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिये राज्य सरकार की ओर से 25 एकड़ ज़मीन भी उपलब्ध करवा दी गई है। इस हेलीहब के बनने से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर-ट्रैफिक को डॉयवर्ट किया जा सकेगा।

ज़िला जल संसाधन योजना 2022-25

चर्चा में क्यों?

18 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अध्यक्षा केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य में स्थाई जल संसाधन प्रबंधन एवं योजना क्रियान्वयन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में 'ज़िला जल संसाधन योजना 2022-25' तैयार की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत राज्य में हर साल जल की कमी के साथ-साथ जलभराव वाले क्षेत्रों के लिये ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाएंगे।
- केशनी आनंद अरोड़ा ने बताया कि जल संसाधन योजना 2022-25 राज्य के 22 ज़िलों के लिये स्थायी जल प्रबंधन और योजना क्रियान्वयन की दिशा में बेहतर कार्य करेगी। इस कार्य योजना के तहत पानी की कमी के साथ जल भराव वाले क्षेत्रों में आगामी तीन साल के दौरान पानी के अंतर में 45 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया है।
- उन्होंने कहा कि इस योजना से पहले साल में 10 प्रतिशत, दूसरे साल में 15 प्रतिशत तथा तीसरे साल में 20 प्रतिशत पानी की कमी और जल भराव की समस्या को दूर किया जा सकेगा।
- अध्यक्षा ने बताया कि ज़िला यमुनानगर और अंबाला में किये गए प्रयासों से दोनों ज़िलों ने जल भराव एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। उन्होंने सभी ज़िलों के लिये एकीकृत और समग्र तीन वर्षीय ग्राम-स्तरीय जल कार्रवाई योजना तैयार करने के निर्देश दिये।
- उन्होंने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले ज़िलों के लिये सतही जल और भूजल के स्थाई जल के उपयोग को शामिल करके एक व्यापक स्तर की योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग बढ़ाकर और अधिक सकारात्मक परिणाम लाए जा सकेंगे।
- अध्यक्षा ने बताया कि राज्य में गैर-पीने योग्य पानी के उद्देश्यों के लिये उपचारित अपशिष्ट जल का प्रयोग किया जाए, ताकि मीठे पानी के संसाधनों पर निर्भरता को कम किया जा सके। इसके लिये प्रत्येक ज़िले से कम-से-कम दो नवीन परियोजनाओं को आमंत्रित किया जाए और इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिक निगरानी की जानी चाहिये।
- मुख्य अभियंता सतबीर सिंह कादियान ने कहा कि जल संसाधन प्राधिकरण एवं जल प्रबंधन विभाग का यह महत्त्वपूर्ण एकसूत्रीय कार्यक्रम है। इस द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना को मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी ज़िलों में 24 अक्टूबर तक लागू किया जाएगा।

हरियाणा ने पालम विहार को जोड़ने वाली मेट्रो विस्तार परियोजना के लिये अंतिम डीपीआर को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रेजांगला चौक, गुरुग्राम से सेक्टर 21 एवं द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिये द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- डीपीआर के अनुसार पालम विहार में रेजंगला चौक और द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन को जोड़ने वाला स्पर या मेट्रो एक्सटेंशन 8.40 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 4 किलोमीटर पालम विहार से गुरुग्राम में सेक्टर 111 और शेष 4.40 किलोमीटर सेक्टर 111 से सेक्टर 21 द्वारका तक होगा। इस पूरे रूट में 7 स्टेशन होंगे।
- यह मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजना गुरुग्राम शहर के अधिकतम हिस्से को दिल्ली और अन्य आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगी। यह गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर के पालम विहार स्टेशन के साथ इंटरचेंज, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर के आईईसीसी स्टेशन के साथ इंटरचेंज और डीएमआरसी ब्लू लाइन के सेक्टर 21 द्वारका स्टेशन एवं एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज करेगा। इस एमआरटीएस का सेक्टर 110 में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ इंटरचेंज भी होगा। ये लिंकेज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में परिवहन प्रणाली की दक्षता को बढ़ाएंगे।

- इससे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी और सेक्टर-21, द्वारका मेट्रो स्टेशन पर चेक-इन सुविधा मिलेगी।
- एमआरटीएस की शुरुआत से बसों की संख्या, आईपीटी, निजी वाहनों का उपयोग, वायु प्रदूषण में कमी और सड़क आधारित वाहनों की गति में वृद्धि होगी तथा इसके परिणामस्वरूप ईंधन की खपत में कमी, वाहन संचालन लागत और यात्रियों के यात्रा समय में कमी के कारण महत्त्वपूर्ण सामाजिक लाभ होंगे। इससे दुर्घटनाओं में कमी, प्रदूषण और सड़क रखरखाव की लागत सामान्य रूप से समाज के लिये अन्य लाभ साबित होंगे।
- बैठक में मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के हिस्से के साथ 1541 करोड़ रुपए की सकल परियोजना लागत को भी मंज़ूरी दी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुबंध एवं अन्य संबंधित दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिये प्रशासनिक सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम, 2022

चर्चा में क्यों ?

19 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम, 2022 बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम, 2022 अधिसूचित होने के उपरांत फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को वित्तीय खर्चों और प्राधिकरण की बैठक को पूरा करने में सक्षम बनाएगा।
- ये नियम प्राधिकरण के सामान्य और विशेष प्रावधानों को परिभाषित करते हैं, जिसमें समय, स्थान, बैठकों के आयोजन, बैठकों की सूचना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपस्थिति, कोरम की स्थिति, बैठक में किये जाने वाले कार्य, प्रश्नों को तय करने की विधि, गैर-सदस्यों की भागीदारी व अवसंरचना विकास योजना आदि की तैयारी शामिल हैं।

हरियाणा कारागार नियम, 2022

चर्चा में क्यों ?

19 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में लागू 'पंजाब जेल नियमावली-1894' को 'हरियाणा कारागार नियम, 2022' से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा कारागार नियम, 2022 राज्य की सभी जेलों में इसके प्रशासन और प्रबंधन, स्टाफ सदस्यों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों, सिविल कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में निवारक निरोध कानूनों के तहत लागू होंगे।
- इन नियमों को हरियाणा कारागार नियम 2022 कहा जाएगा। ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- हरियाणा कारागार नियम, 2022 स्थानीय कानूनों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन और विलोप के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मॉडल जेल नियमावली, 2016 पर आधारित हैं। इन नियमों में नए भर्ती किये गए कैदियों के लिये उनके व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन, स्वास्थ्य जाँच आदि हेतु कक्षों की स्थापना का प्रावधान भी शामिल है।
- इन नियमों के तहत बंदियों के अलगाव के लिये वर्गीकरण, गैंगेस्टरों और कट्टर कैदियों के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं। इसके अलावा कैदियों के अधिकार और कर्त्तव्यों को भी शामिल किया गया है।
- हरियाणा कारागार नियम, 2022 में जेल के आहार में उचित भोजन, इसकी तैयारी और वितरण प्रबंधन का प्रावधान किया गया है तथा महिला, वृद्ध और मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिये भी विशेष प्रावधान किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि अंग्रेज़ी शासन के दौरान अधिसूचित तथा वर्तमान में हरियाणा राज्य में पंजाब जेल नियमावली-1894 लागू थी।

नोट :

हरियाणा में स्थापित होंगे 6 ऑटोमेटिड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन

चर्चा में क्यों ?

20 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के ज़रिये वाहनों की फिटनेस जाँच हेतु राज्य में 6 ऑटोमेटिड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि ये स्टेशन अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, गुरुग्राम और रेवाड़ी ज़िलों में स्थापित किये जाएंगे। इन स्टेशनों पर लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है।
- उन्होंने कहा कि यह स्टेशन पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे तथा केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से भारी मालवाहक वाहनों और भारी यात्री वाहनों का फिटनेस टेस्ट एटीएस से करने को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा मध्यम माल वाहक वाहनों, यात्री वाहनों और हल्के मालवाहक वाहनों के लिये 1 जून, 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसलिये राज्य में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करना अति आवश्यक हो गया है।
- उन्होंने कहा कि भविष्य में स्क्रैप नीति को भी इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है, जिन वाहनों का इन स्टेशनों से फिटनेस परीक्षण नहीं होगा, वे वाहन सीधे स्क्रैप में जाएंगे।
- बैठक में बताया गया कि वर्तमान में रोहतक में एक वाहन फिटनेस स्टेशन संचालित है। इसके अलावा, 6 और नए स्टेशन बनाए जाएंगे। यह स्टेशन आगामी 20 वर्षों के विज़न के अनुरूप तैयार किए जाएंगे तथा ये स्टेशन 3 लेन, 4 लेन या 6 लेन में बनाए जाएंगे।
- एटीएस स्वचालित तरीके से वाहन के फिटनेस की जाँच के लिये कई मशीनों का इस्तेमाल करता है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की जाँच के लिये भी भविष्य में कई नए उपकरणों को शामिल किया जा सकता है। एटीएस मैकेनिकल इक्यूप्मेंट्स के ज़रिये वाहन की फिटनेस की जाँच करने के लिये सभी जरूरी परीक्षणों को ऑटोमैटिक तरीके से करता है।
- बैठक में बताया गया कि इन स्टेशनों में वाहनों की फिटनेस जाँच करवाने के लिये आने वाले लोगों के लिये सुविधाएँ मुहैया करवाने पर भी प्रारूप तैयार किया गया है। इनमें एटीएम, लॉन्ज, कैफेटेरिया इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

नेचुरल गैस का उपयोग करने वाली हरियाणा की औद्योगिक इकाईयों को वैट में 50 प्रतिशत मिलेगी छूट

चर्चा में क्यों ?

22 अक्तूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में उन औद्योगिक इकाईयों को मूल्य संवर्धन कर (वैट) में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट की बजाय नेचुरल गैस से पूरा करेंगी।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना एमएसएमई सहित पूरे उद्योगों पर लागू होगी तथा इसकी अधिसूचना तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
- उल्लेखनीय है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के उपयोग को प्रतिबंधित है। अब जो उद्योग अपनी ऊर्जा की आवश्यकता सीएनजी, पीएनजी से पूरा करेंगे उनको वैट में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- इसी प्रकार, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनियों को प्रति वर्ष विभिन्न मदों में 164.66 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने को भी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की।
- इस बैठक में बताया गया कि ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, ईवी वाहनों को आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है।

नोट :

- यह नीति ईवी प्रौद्योगिकी में नए विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है और मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ईवी विनिर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिये प्रोत्साहित भी करती है।
- इस नीति में ईवी निर्माताओं को फिक्स्ड पूंजी निवेश (एफसीआई), कुल एसजीएसटी, स्टाम्प शुल्क पर प्रोत्साहन देकर विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, रोज़गार सृजन इत्यादि शामिल हैं।
- यह नीति शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बस बेड़े को शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सैल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का प्रयास किया जाएगा।
- इसके अलावा, सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ईएम) शहरों में शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), ई-मोबिलिटी हासिल करने के लिये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिये चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल एप

चर्चा में क्यों?

23 अक्तूबर, 2022 को हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि आगामी सूर्य ग्रहण मेला-2022 के तमाम अहम पहलू कुरुक्षेत्र प्रशासन की कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल एप पर देखें जा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस मोबाइल एप पर सूर्यग्रहण मेले से संबंधित तमाम अहम जानकारियाँ अपलोड कर दी गई है। इस एप पर कुरुक्षेत्र कैसे पहुँचें, कुरुक्षेत्र का इतिहास, पर्यटन स्थल और 48 कोस के तीर्थों का पूरा इतिहास देखा जा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि सूर्य ग्रहण मेला-2022 में देश-प्रदेश के लाखों लोग कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर, सन्निहित सरोवर के साथ-साथ आसपास के सरोवरों में स्नान करने के लिये पहुँचे हैं।
- इस सूर्य ग्रहण के महत्त्व और लोगों की श्रद्धा तथा दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये प्रशासन द्वारा कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल एप तैयार की गई है।
- इस मोबाइल एप को कुरुक्षेत्र एनआईसी इन से भी लिंक कर दिया गया है। इस साइट पर जाने के बाद कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल एप को देखा जा सकेगा। यह एप एक एंड्रॉइड एप है।
- कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल एप पर कुरुक्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों की पूरी डिटेल को पढ़ा और देखा जा सकता है। इस एप पर कुरुक्षेत्र आने के तमाम मार्गों और संसाधनों का ब्यौरा भी अंकित किया गया है। इसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत ज़िले में स्थित 48 कोस के तीर्थों का भी ब्यौरा एप पर मिलेगा।
- इस एप पर सूचना केंद्र, महिला हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रुम, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ तमाम अहम दूरभाष नंबर भी अंकित किये गए हैं। इसके साथ-साथ सूर्य ग्रहण मेला के दौरान ब्रह्मसरोवर पर स्थित सभी घाटों की जानकारी भी नक्शे सहित अपलोड की गई है। इस मोबाइल एप पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2022 का शेड्यूल और अन्य जानकारियाँ भी डाली गई हैं।

हरियाणा सरकार ने बच्चों को शिक्षा एवं रोज़गार देने के लिये एक नया मैकेनिज्म तैयार किया

चर्चा में क्यों?

23 अक्तूबर, 2022 को हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने बच्चों को शिक्षा देने से लेकर उन्हें रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिये एक नया मैकेनिज्म तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत परिवार पहचान पत्र में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार 6 वर्गों में विभाजित किया गया है।

- प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार इत्यादि सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुँचाने के साथ-साथ इनका संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेगा।
- राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर ज़ोर देते हुए प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास व कल्याण सुनिश्चित करने हेतु यह मैकेनिज्म तैयार किया है।
- कार्य योजना के अनुसार 6 साल तक की आयु के बच्चों का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। विभाग इन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण पर विशेष ध्यान रखेगा।
- साथ ही, विभाग हर बच्चे की ट्रैकिंग भी रखेगा कि वह बच्चा 6 साल तक की आयु तक घर पर, आंगनवाड़ी में या स्कूल में जा रहा है और उसे जरूरी पोषक आहार उपलब्ध हो रहा है या नहीं।
- इसके अलावा राज्य सरकार बच्चों की डे-केयर के लिये क्रैच स्थापित करने पर भी लगातार ज़ोर दे रही है।
- बच्चों को यदि शुरुआत में ही अच्छा पोषण और शिक्षा मिलेगी तो उसकी बुनियाद मज़बूत बनेगी और वे जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे।
- प्रारंभिक शिक्षा जितनी महत्त्वपूर्ण है, उससे भी कहीं अधिक स्कूली शिक्षा का महत्त्व है। इसलिये कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस विजन के साथ अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 साल से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल की जाएगी।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिये ड्रॉपआउट नीति तैयार कर रहा है, जिसके तहत विभाग हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की विशेष ट्रैकिंग रखेगा, ताकि ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सके।
- विभाग के पास प्रत्येक बच्चे का डाटा रहेगा कि वह स्कूल या आईटीआई या अन्य किसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है या नहीं।
- इस रणनीति से राज्य सरकार को प्रत्येक बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी और यदि किसी कारणवश कोई बच्चा शिक्षण संस्थान से ड्रॉपआउट होता है तो सरकार उस बच्चे को वापस शिक्षण संस्थान में लाने का प्रयास करेगी।
- वहीं शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवाओं के सामने रोज़गार की एक बड़ी समस्या होती है। इस दिशा में युवाओं की मदद के लिये राज्य सरकार ने अब विभागों को जिम्मेवारी सौंपी है।
- 18 साल से 24 साल आयु वर्ग तक के बच्चों का जिम्मा उच्चतर शिक्षा विभाग और 25 साल से अधिक आयु वर्ग का जिम्मा रोज़गार विभाग को सौंपा गया है। ये विभाग युवाओं के रोज़गार के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर भी ज़ोर देंगे।
- शिक्षा के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके विभाग युवाओं को रोज़गारपरक तो बनाएंगे ही, वहीं औद्योगिक इकाइयों के साथ संपर्क स्थापित कर युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने में भी समन्वयक बनेंगे।
- इन सभी गतिविधियों के लिये परिवार पहचान-पत्र अथॉरिटी द्वारा इन विभागों को हर माह डाटा प्रेषित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है परिवार पहचान-पत्र पोर्टल पर राज्य के 70 लाख परिवारों और 2.80 करोड़ सदस्यों का डाटा अपडेट हो चुका है। अधिकतम परिवारों का जाति, जन्म तिथि, आय का सत्यापन पूरा किया जा चुका है।

हरियाणा से देश के सात राज्यों के 11 प्रमुख शहरों के लिये होगी सीधी उड़ान शुरू

चर्चा में क्यों?

25 अक्तूबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा से सात राज्यों के 11 प्रमुख शहरों के लिये सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी की गई है। इन शहरों में अमृतसर, जालंधर, श्रीनगर, जम्मू, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, आगरा, वाराणसी, देहरादून तथा बिहार के गया का नाम शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- हिसार में वर्ष 2023 में एविएशन-हब काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद से एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। गुरुग्राम में हेलीहब बनाने के लिये भी हरियाणा की ओर से केंद्र से सहयोग मांगा गया है, राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इसकी मंज़ूरी मिल जाएगी।

नोट :

- जल्द ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) का सेंटर हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय या पॉलिटेक्निक में खोलने की तैयारी की जा रही है। कुछ औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं, जल्द ही बची हुई भी पूरी कर ली जाएंगी।
- हिसार में एयरपोर्ट शुरू होते ही सीमावर्ती ज़िलों से सैन्य-बलों के कर्मचारियों व अधिकारियों को आने-जाने में सुविधा होगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- केंद्र सरकार राज्य में सिविल एविएशन सेक्टर को भी विकसित करने जा रही है। गुरुग्राम में हेलीहब के निर्माण की तैयारी है, जिसके लिये हरियाणा सरकार की ओर से 25 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करवा दी गई है।

कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में सूर्यग्रहण पर पैनल प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों?

25 अक्तूबर, 2022 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में सूर्यग्रहण के अवसर पर दर्शकों के अवलोकनार्थ व्यापक प्रबंध किये गए। प्रातः काल केंद्र में सूर्यग्रहण मान्यताएं एवं वैज्ञानिक अवधारणा विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शान्तनु शर्मा ने किया।

प्रमुख बिंदु

- उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शनी समाज में फैले अंधविश्वास को दूर कर जनमानस के समक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रभावी तरीके से रखने में सक्षम है।
- इस बार कुरुक्षेत्र में आंशिक सूर्यग्रहण रहा, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय 4:25 पर प्रारंभ हुआ तथा 5.39 पर समाप्त हुआ। इसका अधिकतर संक्रमण 5.28 मिनट तक रहा तथा कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट रही।
- उल्लेखनीय है कि जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है तो चंद्रमा सूर्य को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। इस खगोलीय घटना को विज्ञान की भाषा में सूर्यग्रहण कहा जाता है।
- भागवत पुराण के अनुसार एक बार सूर्यग्रहण के अवसर पर श्रीकृष्ण, बलराम और द्वारका से प्रजाजनों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे।
- इस अवसर पर मत्स्य, उशीनर, कौशल, विदर्भ, शृंजय, कंबोज, कैकेय, कुन्ती, अनर्त आदि भारत के अनेक राज्यों के शासक भी आए। इसी अवसर पर ब्रज से नंद और यशोदा भी अन्य गोप-गोपियों संग कुरुक्षेत्र आए थे, इसलिये ही कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण मेला का आयोजन किया जाता है।
- उपायुक्त ने कहा कि केंद्र द्वारा सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की इस स्थिति को नज़दीक से देखने हेतु एक सेलेस्ट्रोन के दो टेलीस्कोप केंद्र के विज्ञान उद्यान में लगाए गए। केंद्र द्वारा किसी भी दर्शक को नंगी आँख से सूर्य ग्रहण न देखने की सलाह दी गई।
- इस ऐतिहासिक खगोलीय घटना के समय कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्मसरोवर में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संतों से लेकर अन्य श्रद्धालुओं के लिये स्नान की अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। युधिष्ठर घाट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी।
- विदित है कि गीता स्थली कुरुक्षेत्र आस्था और पर्यटन का संगम है। पिछले दिनों पवित्र तीर्थ ज्योतिसर में भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप की मूर्ति का अनावरण किया गया था। आगे यहाँ पर थ्री-डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में इस शो का उद्घाटन किया जाएगा। इस शो में महाभारत और श्रीमद्भगवद गीता से जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसके लिये अत्याधुनिक तकनीक जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राफिक इमेज, रोबोटिक और ड्रोन आदि का इस्तेमाल किया जाएगा।
- ज्योतिसर तीर्थ पर 2019 से एक लाइट एंड साउंड शो चल रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ज्योतिसर तीर्थ का परिक्रमा पथ भी बनवाया है। तीर्थ पर लाइटिंग का कार्य किया गया है और प्राचीन वट वृक्ष की सुरक्षा के लिये दीवार भी तैयार करवाई गई है।
- उल्लेखनीय है कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की नगरी का विकास करने के लिये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड द्वारा 48 कोस सर्किट के तहत 164 स्थानों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
- कृष्णा सर्किट योजना के तहत हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र को ऐसा तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। कुरुक्षेत्र में तिरुपति बालाजी का एक मंदिर बन रहा है एवं इस्कॉन मंदिर, अक्षरधाम मंदिर बन चुके हैं। गीता ज्ञान संस्थानम भी गीता के ज्ञान के प्रसार के लिये बहुत बड़ा संस्थान बनने वाला है। यहाँ रिसर्च का काम भी चल रहा है।

HAU ने गेहूँ की किस्म WH1270 का बीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिये 9 कंपनियों से किया समझौता

चर्चा में क्यों ?

26 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) हिसार के कुलपति प्रो. बीआर कांबोज ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अगले सीजन में भरपूर मात्रा में बीज उपलब्ध करवाने के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तकनीकी व्यवसायीकरण को बढ़ावा देते हुए निजी क्षेत्र की 9 प्रमुख बीज कंपनियों से समझौता किया है।

प्रमुख बिंदु

- कुलपति प्रो. बीआर कांबोज ने कहा कि इस किस्म की पैदावार व रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए इसकी मांग अन्य राज्यों में भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनज़र अगले सीजन में भरपूर मात्रा में बीज उपलब्ध करवाने के लिये विश्वविद्यालय ने निजी क्षेत्र की इन बीज कंपनियों से समझौता किया है।
- विश्वविद्यालय ने डब्ल्यूएच 1270 के बीज उत्पादन एवं विपणन के लिये उत्तम सीड्स (हिसार), मॉडल एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (करनाल), कुरुक्षेत्र एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड (इंद्री), शिव गंगा हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड (हिसार), हरियाणा सीड्स कंपनी (करनाल), क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स कंपनी (हिसार), काश्तकार सीड्स विदिशा (मध्य प्रदेश), उन्नत बीज कंपनी (सिरसा) और शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड (हिसार) से समझौता किया है।
- विदित है कि विश्वविद्यालय की तरफ से विकसित गेहूँ की किस्म डब्ल्यूएच 1270 को देश के उत्तर-पश्चिमी मैदानी भाग के सिंचित क्षेत्र में अगेती बिजाई वाली खेती के लिये अधिसूचित किया गया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है।
- विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार इस किस्म की बिजाई करके उचित खाद, उर्वरक व पानी दिया जाए तो इसकी औसत पैदावार 75.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकती है और अधिकतम पैदावार 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। इस किस्म की खास बात यह है कि यह गेहूँ की मुख्य बीमारियाँ पीला रतवा व भूरा रतवा के प्रति रोगरोधी है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

27 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के लिये 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की चार परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 5,618 करोड़ रुपए लागत की हरियाणा 'ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना' का शिलान्यास तथा सोनीपत ज़िले के बड़ी गाँव में बने 590 करोड़ रुपए लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया।
- उन्होंने 315 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने भोंडसी में 106 करोड़ रुपए की लागत के हरियाणा पुलिस आवास परिसर का उद्घाटन भी किया, जिसमें 576 पुलिस कर्मियों के परिवार रह सकेंगे।
- इस मौके पर केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल कोच नवीनीकरण कारखाना से बहुत बड़ा इको सिस्टम तैयार होगा तथा रेलवे ने हरियाणा के सात स्टेशनों का कंपलीट रिडेवलपमेंट सेक्शन किया है।
- उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में 262 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का टेंडर फाइनल हो गया है। इसी तरह से गुरुग्राम, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के मास्टर प्लान की तैयारी है।

नोट :

फरीदाबाद में बने आधुनिक बस अड्डे का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

28 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने फरीदाबाद स्थित एनआइटी में पीपीपी मॉडल के तहत 130 करोड़ रुपए की लागत से चार एकड़ में बने बस अड्डे का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- फरीदाबाद एनआइटी आधुनिक बस अड्डे का नाम हरियाणा के उपमुख्यमंत्री स्व. मंगल सेन के नाम पर होगा।
- इस बस अड्डे के अंदर सुविधाओं में यात्रियों के बैठने के लिये वातानुकूलित गैलरी बनाई गई है तथा इसमें यात्रियों की सुविधा के लिये शौचालय, पीने के लिये आरओ का ठंडा पानी, सामान रखने के लिये क्लाक रूम और जलपान की व्यवस्था होगी।
- परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस बस अड्डे से हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के लिये करीब 50 बसों का संचालन होगा तथा यहाँ 17 बस काउंटर होंगे, जहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब प्रदेशों को जाने वाले यात्रियों को बसों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 60 से अधिक सिटी बसों का संचालन भी यहीं से होगा। इस बस अड्डे पर पाँच मंजिला इमारत बनाई गई है।
- इस बस अड्डे के भूतल और प्रथम तल के आधे-आधे हिस्से में डिपो की व्यवस्था होगी। इसमें दो बेसमेंट बनाए गए हैं तथा दोनों बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिये होगा, जहाँ 1000 गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था की गई है।
- एनआइटी बस अड्डा बसों के अलावा व्यावसायिक हब भी होगा। यहाँ अधिकारी, ड्राइवर व कंडक्टरों के लिये विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालय कक्ष, कैंटीन, शौचालय आदि की भी व्यवस्था की गई है। इसके हर तल पर जाने के लिये सीढ़ियों के साथ-साथ लिफ्ट लग चुकी है।
- फरीदाबाद ज़िला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि पूरा बस अडन्न सीसीटीवी की निगरानी में होगा और यह बस अडन्न शहर के लोगों के लिये बड़ी सौगात साबित होगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कि कि राज्य के सभी बस अड्डे अब बस पोर्ट के रूप में जाने जाएंगे तथा इन बस पोर्ट पर एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी।

एनजीटी द्वारा कचरा प्रबंधन को लेकर गठित कमेटी की तीसरी बैठक गुरुग्राम के बंधवाड़ी में आयोजित

चर्चा में क्यों ?

29 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले के बंधवाड़ी मे कचरा प्रबंधन और कचरे का सही ढंग से प्रसंस्करण करने को लेकर राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित कमेटी की तीसरी बैठक आयोजित की गई ।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर जमा कचरे का आकलन वैज्ञानिक तरीके से नए सिरे से करवाया जाएगा तथा इसकी ज़िम्मेदारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को दी गई है, जो एक सप्ताह में इस कार्य को पूर्ण करवाएंगे, जिसके हिसाब से इस कचरे के निस्तारण के लिये नगर निगम गुरुग्राम संशोधित एक्शन प्लान तैयार करेगा, जिसमें हर गतिविधि के लिये समय सीमा निर्धारित होगी।
- हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसके सदस्यों में जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के एसीएस विनीत गर्ग, शहरी स्थानीय निकाय के एसीएस अरुण गुप्ता, गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त मुकेश आहुजा, फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त जितेंद्र दहिया, गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह तथा सीपीसीबी के क्षेत्रीय निदेशक शामिल हैं।
- कमेटी की बैठक में बंधवाड़ी में कचरे के सही ढंग से निस्तारण से लेकर वहाँ पर लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने और विकेंद्रित कचरा प्रसंस्करण, कचरे से निकलने वाले आरडीएफ के निस्तारण, लीगेसी वेस्ट, लिगेसी लीचेट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने, अग्निशमन के प्रबंध करने आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

नोट :

- इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बंधवाड़ी में जमा पूरे लीगेसी वेस्ट का प्रसंस्करण मार्च 2023 अंत तक पूरा करने के प्रयास किये जाएंगे।
- बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम तथा फरीदाबाद ज़िलों में विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण प्रणाली अपनाने पर कार्यवाही चल रही है, जिसके लिये एक स्थान पर कचरा न ले जाकर दोनों शहरों में छोटे-छोटे कचरा प्रसंस्करण प्लांट लगाए जाएंगे। कचरा प्रसंस्करण के लिये सात अलग-अलग प्रसंस्करण साइटों की पहचान की गई है। हर साइट के लिये सॉलिड वेस्ट और लीचेट ट्रीटमेंट की योजना बनाई गई है।
- ज्ञातव्य है कि गुरुग्राम तथा फरीदाबाद, दोनों शहरों से प्रतिदिन लगभग 2000 मीट्रिक टन कचरा आता है।
- बैठक में बताया गया कि बंधवाड़ी में लीचेट ट्रीटमेंट के लिये 200-200 केएलडी क्षमता के दो डीटीआरओ प्लांट संचालित हो रहे हैं तथा इसके अलावा लगभग 150 केएलडी क्षमता का लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट भी 30 नवंबर तक कार्यरत् हो जाएगा। कुल मिलाकर लीचेट ट्रीटमेंट की 550 केएलडी क्षमता हो जाएगी। इसके बाद प्रतिदिन निकलने वाला लीचेट साथ-की-साथ ही शोधित किया जा सकेगा।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हर सप्ताह लीचेट ट्रीटमेंट को लेकर रिपोर्ट देंगे और जहाँ तक लिगेसी लीचेट का सवाल है, उसे टैंकरों में भरकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर भेजा जाएगा, जहाँ पर जीएमडीए द्वारा उसके ट्रीटमेंट के लिये डीटीआरओ प्लांट लगवाया जाएगा।
- ये लीचेट वाले टैंकर बंधवाड़ी प्लांट से एसटीपी पर पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरणविदों का सहयोग लिया जाएगा और इस लीचेट के सैंपल टेस्ट करने के बाद ही जब इसमें टॉक्सिक पदार्थ निर्धारित मंज़ूरशुदा मात्रा में होंगे, तब ही इसे सीवरेज में डाला जाएगा, अन्यथा नहीं।
- बैठक में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें इकोग्रीन कंपनी की तरफ से बताया गया कि 10 नवंबर से पहले ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिये जाएंगे तथा इसके बाद 31 दिसंबर, 2022 से पहले प्लांट लगाने का कार्य धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा।

आपात स्थिति में हर ज़िले में हेलीपैड सुविधा प्रदान करने वाला हरियाणा बनेगा देश का पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

29 अक्टूबर, 2022 को राज्य के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि भविष्य में युद्ध व आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग सुविधा प्रदान करने के लिये प्रत्येक ज़िले में हेलीपैड बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा।

प्रमुख बिंदु

- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में इस प्रकार का आधारभूत ढाँचा विकसित होने से युद्ध व आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जा सकेगी तथा सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस लाइन में हेलीपैड बनने से इन हेलीपैड की सुरक्षा के भी पूरे इंतज़ाम रहेंगे।
- इन हेलीपैड पर रात्रि के समय लैंडिंग करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी भी संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने लैंडिंग सुविधा के लिये ज़िला पुलिस लाइन में हेलीपैड स्थापित करने की संभावना पर तेज़ी से कार्य करने के निर्देश दिये।
- विदित है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में आपात स्थिति से निपटने के लिये देश के हर ज़िले में एक हेलीपैड बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था। इस दिशा में हरियाणा सरकार ने आश्वस्त करते हुए सर्वप्रथम पहल करने की इच्छा व्यक्त की थी।
- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और अवधारणाओं को राज्य में लागू करने में सदैव अग्रणी रही है। हर ज़िले में हेलीपैड स्थापित करने के लिये गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को आधारभूत ढाँचा विकसित करने के लिये निर्देश दे दिये गए हैं।
- उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिये हरियाणा में संस्थान स्थापित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिये हिसार, सिरसा और पिंजौर में जगह चिह्नित करने के निर्देश दिये, जिससे राज्य के युवाओं के साथ-साथ अन्य राज्यों के युवा भी इस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस संस्थान के बनने से हरियाणा उड्डयन क्षेत्र में और मज़बूत बनेगा।
- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत एयर कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिये अप्रैल 2023 से हिसार से नए मार्ग की पहचान हेतु 7 अन्य राज्यों के साथ समझौता करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस कार्य योजना के सफल होने से प्रदेश के नागरिकों को हवाई यात्रा करने की व्यापक सुविधा मिलेगी।

नोट :